

225 (क) लेख भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान

225 (ख) लेख बाबा रामदेव उत्थान और पतन

225 (ग) लेख कायरता की पटकथा पर माओवाद का मातम
—संजय द्विवेदी

225 (घ) प्रश्नोत्तर श्री चिन्मय व्यास, मालदेवता, देहरादून, उत्तरांचल

225 (च) प्रश्नोत्तर (2) श्री राजेन्द्र भारतीय, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर M0प्र0

225 (छ) प्रश्नोत्तर श्री ओमपाल सिंह जी मेरठ

225 (ज) प्रश्नोत्तर श्री ओमपाल सिंह जी मेरठ

225 (झ) प्रश्नोत्तर श्री ओमपाल सिंह जी मेरठ

225 (ट) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर— परमाणु उर्जा पर

भ्रष्टाचार, समस्या और समाधान

आज संपूर्ण भारत में भ्रष्टाचार सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा लगता है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है। रामदेव जी के अनशन और अन्ना हजारे के आंदोलन ने इस विषय को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। हर आदमी इस बीमारी की चर्चा करने लगा है। किन्तु यदि गहराई से सोचा जाय तो भ्रष्टाचार की समस्या वैसी नहीं जैसी दिखती है अथवा जिस तरह प्रचारित की गई है।

भारतीय राजनीति का एक सर्वमान्य चरित्र है कि वह (1) समाज रूपी बिल्लियों के बीच स्वयं को बंदर के रूप में मानती है (2) राजनीति किसी भी समस्या का समाधान विपरीत आचरण वाली व्यवस्था से खोजती है। बिल्लियों के बीच बंदर की भूमिका इस प्रकार होती है कि वह बिल्लियों की रोटी को कभी बराबर नहीं होने देता किन्तु बंदर इतना चालाक होता है कि वह हमेशा बिल्लियों की रोटी बराबर करता हुआ दिखना चाहता है भले ही रोटी कभी बराबर न हो। बंदर यह भी प्रयास करता है कि छोटी रोटी वाली बिल्ली के मन में असमानता रूपी असंतोष की ज्वाला निरंतर जलती रहे। भारतीय राजनीति पूरी इमानदारी से तीनों प्रयत्न करती रहती है। स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही समाजवाद के नाम पर आर्थिक विषमता दूर करने के गंभीर प्रयत्न शुरू हुए जो अब तक जारी हैं किन्तु आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती रही। साथ ही हमारे राजनेताओं ने गरीबों के मन में सम्पत्तियों के विरुद्ध असंतोष की ज्वाला भी लगातार सफलता पूर्वक जलाए रखी। इसी तरह भारतीय राजनीति ने प्रयत्न किया कि आर्थिक समस्याओं का आर्थिक समाधान, प्रशासनिक समस्याओं का प्रशासनिक समाधान तथा सामाजिक समस्याओं का सामाजिक समाधान किसी भी परिस्थिति में न हो। राजनैतिक व्यवस्था निरंतर सक्रिय रही कि आर्थिक समस्याओं का सामाजिक प्रशासनिक समाधान हो, सामाजिक समस्याओं का आर्थिक प्रशासनिक समाधान हो तथा प्रशासनिक समस्याओं का सामाजिक आर्थिक समाधान हो। आर्थिक असमानता आर्थिक समस्या है। भारतीय राजनैतिक व्यवस्था आर्थिक असमानता कालेधन अथवा भ्रष्टाचार को प्रशासनिक तरीके से हल करना चाहती है जबकि आतंकवाद नक्सलवाद को आर्थिक सामाजिक तरीके से हल तथा दहेज बाल विवाह शराब जुआ आदि को आर्थिक प्रशासनिक तरीके से हल करने की कोशिश करती है।

इन सबके साथ साथ राज्य का यह भी चरित्र होता है कि वह समस्याओं को हल करता हुआ तो दिखे किन्तु होने न दे। राज्य हमेशा ऐसे समाधान की कोशिश करता है कि उक्त समाधान से ही एक नई समस्या का जन्म हो और राज्य उक्त नई पैदा समस्या के समाधान में इस तरह सक्रिय हो कि उससे एक और नई समस्या पैदा हो। नई नई समस्याएँ पैदा होती रहे और राज्य उन समस्याओं के समाधान के नाम पर समाज के अधिकारों में थोड़ी थोड़ी कटौती करता रहे। स्वतंत्रता के बाद के साठ बासठ वर्षों से यही क्रम चल रहा है जो आज भी यथावत जारी है। आर्थिक विषमता आर्थिक प्रयत्नों के आधार पर दूर होनी चाहिये थी किन्तु राज्य ने आर्थिक विषमता दूर करने के लिये समाजवाद का नारा देकर प्रशासनिक कानून बनाने शुरू कर दिये। प्रशासनिक व्यवस्था यदि आर्थिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय होती है तो भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करती है। भ्रष्टाचार का एक ऐसा चक्र चल पड़ता है कि दोनों एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। अन्डे से मुर्गी और मुर्गी से अन्डा। राजनीतिज्ञ कभी यह निर्णय नहीं होने देता कि अन्डा या मुर्गी में से मारने की पहल कहाँ से करे?

जब संपूर्ण विश्व जानता है कि भ्रष्ट व्यवस्था समाजवाद नहीं ला सकती। इसके विपरीत भ्रष्टाचार आर्थिक विषमता दूर करने में सबसे बड़ी बाधा है। ये इतने पड़े लिखे नेता नेहरू, अम्बेडकर, लोहिया आदि इस बात को क्यों नहीं समझ सके कि पहले भ्रष्टाचार कम करना होगा और उसके बाद समाजवाद की दिशा में बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद तत्काल ही भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। हमारे नेता गण समाजवाद की दिशा में तेजी से चलने लगे। ये लोग जितनी ही समाजवाद की दिशा में तेज छलांग लगाते उससे कई गुना अधिक तेज गति से भ्रष्टाचार बढ़ता और भ्रष्टाचार के परिणाम स्वरूप आर्थिक विषमता बढ़ती जाती। मैं नहीं कह सकता कि ये बड़े बड़े नेता इस बात को समझ नहीं पा रहे थे अथवा समझना नहीं चाहते थे। पुरानी बातों को तो छोड़िये। आज सोनियाँ जी, दिग्विजय सिंह, सुषमा स्वराज्य, प्रकाश कारत, आदि भ्रष्टाचार दूर करने की बात बहुत करते हैं किन्तु समाजवाद के प्रयत्न साथ में लेकर। स्पष्ट है कि ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। आर्थिक विषमता दूर करने के कोई भी प्रयत्न तंत्र को अधिक अधिकार सम्पन्न बनायेंगे ही और तंत्र की यह अधिकार वृद्धि ही भ्रष्टाचार रूपी विष बेल की खाद पानी का काम करती है। एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बना दी गई है। यह परिषद नित नये नये समाजवादी प्रस्ताव लाती है। गरीबों को इतना अनाज दो, इतनी सुविधा दो, अमीरों पर इतना क्रय विक्रय कर लगाओ। यह सुविधा यह कारारोपण किसके माध्यम से होगा? क्या इससे तंत्र का लोक में हस्तक्षेप नहीं बढ़ेगा? क्या इससे भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा? ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार रोको। इनसे पूछा जाय कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये क्या यही भ्रष्ट तंत्र सफल होगा? पहले भ्रष्टाचार दूर करें कि पहले तुम्हारा समाजवाद लावे? दोनों साथ साथ संभव नहीं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

एक है बाबा रामदेव। इन्हे शरीर विज्ञान का क्या ज्ञान हो गया कि ये अपने को समाजशास्त्र राजनीति शास्त्र का भी ज्ञाता समझने लगे। जबकि सच्चाई यह है कि इन्हे राजनीति शास्त्र का तो ज्ञान शून्य ही है किन्तु समाज शास्त्र का ज्ञान भी न के बराबर है। भारत के विदेशों से काला धन वापस लाया जावे। इस बात के पीछे पड़े हैं। इन्हे यह भी पता नहीं कि काला धन क्या है, कैसे बनता है, क्या परिणाम होता है तथा वर्तमान में बनकर बाहर जा रहा है कि नहीं? भारत में स्वतंत्रता के बाद काला धन उसी दिन से बनना शुरू हुआ जबसे समाजवाद की धुन सवार हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत में सन सैतालीस में दो हजार रु वार्षिक आय पर उन्नीस प्रतिशत तथा बीस हजार से अधिक पर छियासी प्रतिशत इन्कम टैक्स लगता था। हमारे नेताओं ने सन बावन तक यह टैक्स रेट बढ़ाकर चार हजार की आय पर सवा बाइस प्रतिशत तथा चालीस हजार से उपर की आय पर बान्नेवे प्रतिशत कर दिया। इस कर के उपर सरचार्ज भी लगाया गया। कुल इन्कम टैक्स पंचान्नवे प्रतिशत तक हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि समाजवाद के नाम पर पागल सरकार ने यह नहीं सोचा कि इतने कराधान से भारत में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कालाधन बढ़ेगा, अव्यवस्था हो जायगी। इन्हे तो बस निकम्मे प्रशंसकों तथा रूस चीन की वाहवाही मात्र चाहिये थी। परिणाम हुआ कि भ्रष्टाचार बढ़ा, कालाधन बढ़ा, अव्यवस्था बढ़ी। इन लोगों ने समाज में यह धारणा भी फैलाई कि न परिश्रम से धन बढ़ सकता है न बुद्धि से। धन तो सिर्फ धूर्तता या अपराध से ही बढ़ सकता है। इस प्रचार का परिणाम हुआ कि धूर्तता और अपराध की ओर आम लोग अधिक बढ़े। सरकार के पास पैसा बढ़ा तो उसके पास चापलूस निकम्मे परजीवियों की फौज इकट्ठी हुई जो समाजवाद की माला जपती रही और बिना मेहनत के सरकारी मेहमान बन गईं।

स्पष्ट है कि जब तक भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक हमारी कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार राजनैतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी है। इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट है कि जब तक समाज की सामाजिक समस्याओं के समाधान में तंत्र की भूमिका नहीं घटती तब तक भ्रष्टाचार कम हो ही नहीं सकता। हमारे पास आर्थिक विषमता रोकने का तब तक कोई उपाय नहीं जब तक भ्रष्टाचार न घटे। यदि भ्रष्टाचार के रहते आर्थिक विषमता रोकने के प्रयत्न जारी रहे तो भ्रष्टाचार बढ़ना निश्चित है। हमें कुछ समय के लिये भ्रष्टाचार और आर्थिक विषमता में से एक को चुनकर उस के समाधान में ताकत लगानी होगी और स्पष्ट है कि

ऐसी हालत में भ्रष्टाचार को रोकना ज्यादा कारगर कदम होगा। कालाधन आज भी बन रहा है और बाहर जा रहा है। ना समझ लोग कालाधन लाने का आंदोलन कर रहे हैं। पहले भारत में कालाधन बनना तो रोको। कालाधन बनता रहे, विदेशी बैंको में जाता रहे और हम वापस लाने की लड़ाई लड़ते रहे। काले धन का बनना भी रोक सकता है और बाहर जाना भी यदि हम एक बार कुछ समय के लिये सुरक्षा और न्याय को छोड़कर सारे खर्च रोक दें। इससे इन्कम टैक्स का रेट घटकर पांच प्रतिशत तक का हो सकता है या शुन्य भी संभव है। देखिये कि कालाधन भारत में लौटता है कि नहीं। देखिये कि भ्रष्टाचार घटता है कि नहीं। मैं मानता हूँ कि इस कदम से गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत चौड़ी होगी। किन्तु हम दोनो काम एक साथ कर ही नहीं सकते। ऐसी हालत में हमें कुछ स्पष्ट निर्णय तो लेने ही होंगे। यदि टैक्स खतम करने से सारी समस्या दूर हो सकती है तो हमारे दो महत्वपूर्ण प्राण अन्ना जी और रामदेव जी की जान जोखिम में क्यों डाली जाय। यदि साठ वर्ष तक समाजवाद नहीं आया, गरीब अमीर के बीच की खाई बढ़ती रही तो पांच वर्ष और झेल लेंगे। कम से कम भ्रष्टाचार और कालेधन से तो छुटकारा मिलेगा। अन्ना जी की टीम तो इस दिशा में कुछ समझ भी रही है किन्तु रामदेव जी तो इस लाइन पर सोचना ही नहीं चाहते। सरकार में भी मनमोहन सिंह जी की टीम इस लाइन पर काम करना चाहती है किन्तु राहुल गांधी की टीम इसके ठीक विपरीत सोच रही है। परिणाम यह होगा कि न समाजवाद आयागा न ही भ्रष्टाचार और कालाधन रुकेगा। भारत की राजनैतिक व्यवस्था में इतनी ताकत नहीं कि वह समाजवाद का इतना बड़ा पत्थर पैर में बांधकर सरपट दौड़ लगा सके।

मेरे विचार में तो समस्याओं के समाधान की शुरुआत यही से संभव है कि कुछ समय के लिये आर्थिक विषमता की छूट कर दी जावे, जनकल्याण के कार्यों पर खर्च न्यूनतम हो, अधिकतम निजीकरण कर दे, टैक्स वसूली के प्रयत्न कम कर दे, इन्कम टैक्स न्यूनतम कर दे। साथ ही राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसी परजीवी संस्थाओं को कुछ समय के लिये रोक दे या उसका स्वरूप बदल दे। यदि हमने ऐसे कुछ कदम उठा लिये तो अनेक समस्याएँ अपने आप सुलझनी शुरू हो जायगी।

याद रखिये कि पहले अंडा कि पहले मुर्गी यह निर्णय करना ही होगा। साठ बासठ वर्षों से निकम्मे लोगों ने यह निर्णय नहीं होने दिया। एक गुट अण्डा से पहल करना चाहता है तो दूसरा मुर्गी से। हम एक स्पष्ट निर्णय लेना शुरू करें तभी इन समस्याओं का समाधान संभव है।

बाबा रामदेव उत्थान और पतन

रामदेव जी का उत्थान जिस तेज गति से हुआ, पतन की गति उससे भी बहुत ही तेज थी। ऐसा लगा जैसे एकाएक गुंवारा फूट गया हो और गुंवारे की हवा को पकड़ते पकड़ते रामदेव जी खुद ही तबाह हो गये हों। रामदेव जी ने जिस महल को खड़ा करने में इतने वर्ष लगाये थे वह महल राजनैतिक वजन न सहालने के कारण एकाएक हिलने लगा और बाबा रामदेव जान बचाकर उस से बाहर कूद गये। रामदेव जी बड़ी शान्ति से अपने योग व्यवसाय में सफलता और सम्मान पूर्वक बढ रहे थे। एकाएक उन्हें क्या सूझी कि उन्होंने लालच में आकर राजनीति रूपी कंबल को पकड़ लिया। किन्तु वह काला कम्बल न होकर भालू निकला। अब रामदेव जी तो कम्बल को छोड़ना चाहते हैं किन्तु वह भालू रूपी कम्बल रामदेव जी को छोड़ने को तैयार नहीं।

बाबा रामदेव न कभी सन्त रहे न हैं। पांच वर्ष पूर्व ज्ञानतत्व एक सौ सात में मैने रामदेव जी की समीक्षा की थी। मेरी वह समीक्षा इस प्रकार थी। (प्राचीनकाल से ही भारत में स्वास्थ्य में योग के महत्व को बढ-चढ कर स्थान दिया गया। योग को शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्याओं तक का समाधान बनाने के प्रयत्न में योग के शारीरिक, मानसिक प्रभाव सूत्र आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के पूर्व ही यम और नियम के पालन की अनिवार्यता घोषित की गई। योग के विषय में सामान्य-सा ज्ञान रखने वाला भी जानता है कि यम और नियम का आंशिक पालन ही सामाजिक समस्याओं का अच्छा समाधान है तो पूरी तरह पालन की तो बात ही अलग है। समाज में ज्यों-ज्यों चरित्र की गिरावट आती गयी, त्यों-त्यों यम और नियम पालन कठिन होता गया और धीरे-धीरे यम और नियम पालन असंभव होने से आसन, प्राणायाम प्रत्याहार के स्वास्थ्य वर्धक योग प्रयोग भी कमजोर पड़े।

भारत में अनेक योग प्रमुखों ने यम नियम को छोड़कर योग की शिक्षा देनी शुरू की किन्तु वे लोग भी योग को उतना सर्वसुलभ नहीं कर सके, क्योंकि वे लोग योग के शारीरिक लाभ की अपेक्षा मानसिक लाभ पर अधिक जोर देते रहे। बाबा रामदेव ने माना कि योग को सामाजिक, मानसिक लाभ की जटिल प्रक्रिया से निकालकर यदि शारीरिक लाभ तक सीमित कर दिया जाये तो यह सर्व सुलभ हो सकता है तथा धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से इसका मानसिक सामाजिक प्रभाव भी संभव है। रामदेव जी ने बहुत तेज गति से इस दिशा में काम शुरू किया। आसन और प्राणायाम को इन्होंने परिवर्तन का मुख्य सूत्र बनाया और प्रत्याहार को भी उसके साथ जोड़ लिया। उन्होंने अपने संशोधित योग प्रयत्न के प्रचार प्रसार के लिए अत्याधुनिक मीडिया तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया। उनके प्रयत्न और प्रचार-प्रसार का व्यापक प्रभाव हुआ। सारे भारत में स्वास्थ्य के लिए योग की महत्ता को स्वीकार किया गया। बड़े से छोटे तक में योग से स्वास्थ्य की दिशा में सक्रियता बढी। अनेक मुसलमान भी छिप-छिप कर योग करने लगे। भारत की यह चमत्कारिक अनुगूँज सम्पूर्ण विश्व में सुनायी देने लगी। अनेक सरकारें स्वास्थ्य के लिए योग के सस्ते, स्वाभाविक, सुलभ और प्राकृतिक तरीके की ओर आकर्षित भी हुईं। भारत में बड़ी संख्या में साधारण लोग भी योग की शिक्षा देने और लेने लगे। वर्तमान में पहली बार योग योगियों से निकलकर सामान्य नागरिक के घर तक पहुँचा। योग के प्रत्यक्ष प्रभाव से सामान्य जन ने स्वास्थ्य लाभ किया यह निर्विवाद है। साथ ही योग के अप्रत्यक्ष प्रभाव का मानसिक और सामाजिक लाभ भी दिखने लगा-यह भी निर्विवाद ही है।

रामदेव जी के योग के व्यापक प्रभाव से उनको अप्रत्याशित ख्याति भी मिली और धन भी। बड़े-बड़े व्यापारी भी रामदेव जी के इर्द-गिर्द मंडराने लगे। रामदेव जी भी अपनी ख्याति का लोभ संवरण नहीं कर सके। उन्होंने अपने योग का विस्तार आयुर्वेद तक कर दिया और आम लोगों को आयुर्वेदिक दवाओं के नुस्खे बताते-बताते आयुर्वेदिक दवा निर्माण तक जा पहुँचे। सन्यासी बाबा रामदेव यम के पांच प्रारंभिक सूत्र, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह में से अपरिग्रह को भूल बैठे। उन्होंने धन इकट्ठा किया या नहीं यह तो मुझे पता नहीं, किन्तु जिस तरह उन्होंने योग से आयुर्वेद की ओर दिशा मोड़ी और आयुर्वेद से आगे जाकर भारतीय संस्कृति की सुरक्षा की ओर छलांग लगाई वह उनकी सांसारिकता की दिशा मानी जा सकती है। ये सारी दिशाएँ गलत नहीं थीं क्योंकि ये दिशाएँ लोक कल्याणकारी थीं किन्तु लोक कल्याण के लिए भी उन्होंने जिस सीमा तक स्वयं को आयुर्वेदिक दवा कारखाने के साथ जोड़ा वह उनकी भूल मानी जानी चाहिए।

रामदेव जी ने जिस तरह विदेशी पेयों का विरोध किया उसका न योग चिकित्सा से संबंध था न ही आयुर्वेद से। यदि आयुर्वेद के लिए शीतल पेय का विरोध करते होते तो उसकी भाषा भिन्न होती किन्तु रामदेव जी का विदेशी शीतल पेय विरोध आयुर्वेद से अधिक स्वदेशी पर केन्द्रित था। स्वाभाविक ही था कि रामदेव जी के प्रचार ने अनेक प्रकार के दुकानदारों को चिन्तित किया। रामदेव जी के योग से तो बहुत कम दुकानदार प्रभावित थे, किन्तु इनके आयुर्वेद और स्वदेशी से अनेक पेशेवर एलोपैथी वाले, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा विदेशी राजनीति करने वालों के समक्ष खतरा मंडराने लगा। रामदेव जी के स्वदेशी और भारतीय संस्कृति के धुंआधार प्रचार ने साम्यवादी विचारधारा को भी चिन्तित किया। साम्यवाद ने रामदेव जी के आयुर्वेदिक दवा कारखाने में कानूनी अनियमितताओं के सहारे तोड़-फोड़ शुरू कर दी। ऐसे कारखानों में श्रम कानूनों का उल्लंघन होता ही है। ऐसा एक भी कारखाना नहीं जो सभी कानूनों का अक्षरशः पालन कर सके। मजदूरों में अपनी घुसपैठ बनाकर साम्यवादियों ने बाबा रामदेव की दवा कारखानों की गतिविधियों की गुप्त जानकारी भी ली और धीरे-धीरे जानकारी एकत्रित करके एक दिन उसका विस्फोट कर दिया।

आयुर्वेदिक दवा कारखाने में मजदूर हितों का उल्लंघन सामान्य भारतीय के मन में रामदेव जी की छवि गिराने के लिए अपर्याप्त मानकर ही साम्यवाद ने दवा में पशु और मानव हड्डी के प्रयोग जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। मैं नहीं कह सकता कि साम्यवादियों का उद्देश्य अपने मजदूरों के हित से अधिक जुड़ा था या रामदेव जी की प्रतिष्ठा के आघात से। किन्तु मुझे ऐसा लगता है कि साम्यवादी भी अपने कार्य को मजदूरों से बढ़ाते-बढ़ाते रामदेव पतन तक उसी तरह भ्रम में बढ़ाते चले गये जिस भ्रम में रामदेव जी ने योग से आयुर्वेद और आयुर्वेद से भारतीय संस्कृति रक्षण तक बढ़ाया था। किन्तु अपूर्ण तैयारी और साम्यवाद की सामाजिक विश्वसनीयता के अभाव ने उनके ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को विफल कर दिया। साम्यवादियों ने जो आक्रमण किया उसमें कई कमजोरियाँ थीं

क. उनका आक्रमण रामदेव जी के कानूनी उल्लंघन तक सीमित था। दवा में पशु या मानव हड्डी का प्रयोग हुआ यह आयुर्वेदिक दवाओं के लिए बहुत अधिक चौंका देने वाली बात नहीं थी। यह मात्र एक कानून का उल्लंघन था कि दवा पर जानकारी लिखना कानूनी बाधता है।

ख. साम्यवादी रामदेव जी की कानूनी अनियमितताओं को जितना गंभीर विषय बनाना चाहते थे, उसमें उसने स्वयं ही कानूनी प्रक्रियाओं की अनदेखी करने की भूल कर दी। दवा किसी शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत खरीदकर तथा सील कराकर जाँच करानी चाहिए थी जो उन्होंने इस तरह पूरी की जैसे बंगाल में जाँच हो रही हो। इस कमी के कारण रामदेव जी को नमूने इन्कार करने का मजबूत बहाना मिल गया।

ग. साम्यवादी विदेशों से धन लेकर राजनीति करने के लिए विख्यात है। फिर भी आजतक इन पर ऐसा कोई आरोप नहीं कि इन्होंने कभी पूँजीवादी देशों या कम्पनियों से धन लिया हो किन्तु विश्वसनीयता के अभाव ने रामदेव जी को प्रचारित करने का अवसर दे दिया कि साम्यवादियों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से साठगाँठ की है।

घ. साम्यवादियों की भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों के विरुद्ध सोच सर्वविदित है। मांसाहार या आयुर्वेद के विषय में इनकी सोच कभी सकारात्मक नहीं रही। भारतीय सांस्कृतिक भावना की सुरक्षा की इतनी चिन्ता को भारतीय जनमानस स्वाभाविक सोच से अधिक कोई खराब नीयत समझ रहा था। क्योंकि साम्यवाद ने ऐसे ही अन्य सामानों की कभी चिन्ता नहीं की। यदि साम्यवादी वृन्दा जी की अपेक्षा किसी साधु संन्यासी के मुँह से यह रहस्योद्घाटन कराने की चालाकी करते तो शायद कुछ अधिक प्रभाव होता। किन्तु संस्कृति विरोध के लिए प्रसिद्ध संगठन द्वारा आक्रमण किये जाने से रामदेव जी को प्राकृतिक विश्वसनीयता का लाभ हुआ।

च. रामदेव जी के प्रचार से योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की भावना को व्यापक विस्तार मिल रहा था। सामान्य लोगों ने रामदेव जी पर आक्रमण को योग, आयुर्वेद तथा स्वदेशी के विरुद्ध षडयंत्र माना। विशेषकर तब, जब ऐसा आक्रमण योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के विपरीत सोच और आचरण वाले संगठन और व्यक्ति द्वारा किया जावे।

कुल मिलाकर रामदेव जी पर साम्यवादियों का आक्रमण साम्यवादियों के लिए ही घातक हुआ। साम्यवादी अब तक सम्पूर्ण विश्व की राजनीति में सुनियोजित और दीर्घकालिक योजना अनुसार काम करने के लिए प्रसिद्ध हैं। किन्तु इस बार या तो उनकी योजना फेल हुई या वृन्दा जी ने अकेले की योजना पर ही इतना बड़ा आक्रमण कर दिया। कुछ भी हो लेकिन साम्यवाद को इस अनावश्यक और बचकानी हरकत से बहुत क्षति हुई है। लालू प्रसाद यादव ने इस विषय पर सबसे अधिक स्वाभाविक और स्पष्ट टिप्पणी की कि दवा यदि मानव हित में है तो यह चिन्ता का विषय नहीं कि उसमें मानव की हड्डी मिली है या दानव की। अन्य राजनेताओं ने भी जनभावना का आदर किया और रामदेव जी के पक्ष में आवाज उठाई।

इस घटना ने रामदेव जी को तात्कालिक लाभ और दूरगामी क्षति पहुँचाई है। उन्होंने आक्रमण को सफलता पूर्वक झेलकर स्वयं को विजेता के रूप में स्थापित किया है किन्तु इस संघर्ष में उन्हें कई स्थानों पर सत्य का गला भी घोटना पड़ा है। रामदेव जी को कई बार यह असत्य दुहराना पड़ा कि ये दवाएँ उनके कारखाने की नहीं हैं। उन्हें कई बार यह कहना पड़ा कि वे श्रम कानूनों का पूरी तरह पालन करते हैं। उन्हें कई बार यह भी कहना पड़ा कि उनकी दवाओं में मानव या पशु की हड्डियों का कोई अंश नहीं है।

मैं मानता हूँ कि भारत के कानूनी जाल से बचने के लिये असत्य बोलना एक मजबूरी है किन्तु ऐसी असत्य की मजबूरी से भी आत्मबल तो घटता ही है। अब रामदेव जी विदेशी कम्पनियों पर या एलोपैथी पर उतना तीव्र और प्रभावशाली आक्रमण नहीं कर पायेंगे जितना वे पहले करते थे क्योंकि स्वामी जी के योग के यम और नियम से सत्य भी संदेहास्पद हो गया है, अपरिग्रह तो खतरे में था ही। मैं चाहता हूँ कि स्वामी रामदेव जी ने विश्व को स्वास्थ्य के लिये योग का चमत्कारिक नुस्खा देकर जो प्रतिष्ठा प्राप्त की है तथा जनकल्याण किया है उसे विश्व विजेता बनने की दौड़ में क्षति न पहुँचाई जाये।^[2]

मैंने जिस समय यह समीक्षा की थी वह पांच वर्ष पूर्व का समय था। उस समय से लेकर चार जून की घटना तक मुझे छोड़कर किसी ने रामदेव जी की इतनी स्पष्ट समीक्षा नहीं की। मेरे लेख के बाद तो उनके सम्मोहन तथा प्रशंसकों में कई गुना वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो रामदेव जी के अन्दर एक समाज शास्त्री की छवि देखने लगे थे। मैंने उसके बाद भी कई बार लिखा कि रामदेव जी को शरीर विज्ञान का ज्ञान तो है किन्तु समाज शास्त्र का उन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं। रामदेव जी ने अपार धन एकत्रित किया और अन्त तक करते रहे। वे यह भूल गये कि किसी व्यापारी धनवान को राजनैतिक आंदोलन का नेतृत्व कभी नहीं करना चाहिये। इतिहास बताता है कि व्यापारी पूँजीपतियों ने हमेशा पीछे रहकर सत्ता संघर्ष में साथ दिया है। उन्होंने कभी सामने आकर नेतृत्व नहीं किया। व्यापारी पूँजीपति तो हमेशा राज्य की मुठी में रहता है। वह क्या संघर्ष कर पायेगा? रामदेव जी इतिहास बदलना चाहते थे। वे चौबे से छव्वे बनने के लिये राजनीति में कूदें किन्तु दुबे बनकर भी बच जायेंगे ऐसा नहीं लगता। यहाँ तक कि रामदेव जी के कन्धे पर सवार होकर भाजपा भी सत्ता की कल्पना करने लग गई थी। अब भी उसे लगता है कि कुल मिलाकर भाजपा को कुछ लाभ हुआ है। मेरे विचार में रामदेव जी का तो जो कुछ होना था हुआ ही भाजपा को भी इस रामदेव प्रकरण से बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि रामदेव जी भाजपा के कन्धे पर सवार नहीं थे। इसके उलट भाजपा ही रामदेव जी के कन्धे पर सवार थी।

मैंने पांच वर्ष पूर्व जब पहला लेख लिखा था तो मेरे कई साथी नाराज हुए थे। बाद में भी कई साथियों की टिप्पणियाँ आती रहीं। मैं अपने निष्कर्ष पर अडिग रहा। मैं कभी बाबा का आलोचक भी नहीं रहा, विरोध का तो प्रश्न ही नहीं था। किन्तु मुझे बाबा रामदेव के अंदर कभी समाज शास्त्र का न तो ज्ञान दिखा न अनुभव। ऐसा सीधा साधा व्यक्ति यदि समाज विज्ञान से भी आगे बढ़कर राजनीति की कुटिल सीढियों चढ़ने लगे तो भूल सीढी चढ़ने वाले की मानी जायगी। चरित्रवान व्यक्ति को बहुत योजना पूर्वक ही वैश्यालय की चहार दीवारी में घुसने की कोशिश करनी चाहिये। रामदेव जी व्यापार तक तो ठीक थे किन्तु आगे जाकर उन्होंने भूल की। सन पंचान्नवे में मैंने जब व्यवस्था परिवर्तन की आवाज लगाई तो सत्ता प्रतिष्ठान ने मेरे उपर भरपूर आक्रमण किया था। राजनैतिक गलियारों में मुझे एक आर्थिक सम्पन्न व्यापारी माना जाता था। यदि वास्तव में मैं आर्थिक रूप से सम्पन्न व्यापारी रहा होता तो या तो मैं जल्दी ही समझौता कर लेता अन्यथा मेरा भी वही हाल होता जो रामदेव जी का हुआ। सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी और मैं अपने मार्ग पर लगातार बढ़ता रहा। आज भी मैं एकान्त में बैठकर राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र पर गंभीर चिन्तन करता हूँ। मुझे आत्म संतोष है कि आज मेरे विचार संपूर्ण भारत में गंभीरता से सुने जाते हैं। यदि मैं भी धन संग्रह में लग जाऊँ तो चिन्तन विकृत होना स्वाभाविक है और यदि धन संग्रह के साथ साथ सत्ता मोह में भी लिपटने लूँ तो बस भगवान ही मालिक है।

मैं पूर्व में भी कई बार स्पष्ट कर चुका हूँ और पूनः स्पष्ट करूँ कि वर्तमान स्थितियों में कोई भी समाधान नहीं दिखता जिस पर आंख बन्द कर के चला जा सके। व्यक्ति के रूप में तो कोई है ही नहीं किन्तु विचारधारा के रूप में भी नहीं है। निराश होकर चुप बैठना भी उचित नहीं। समाज के समक्ष समस्याएँ बढ़ नहीं रहीं बल्कि योजनापूर्वक बढ़ाई जा रही हैं। और इन समस्याओं को बढ़ाने में संसदीय प्रणाली सबसे आगे है। हम न तो तत्काल टकराव की स्थिति में हैं न ही निराश होकर चुप बैठ सकते हैं। समस्याएँ हैं और लगातार बढ़ाई जा रही हैं यह निश्चित है। किसी भी बीमारी के तीन प्रकार के इलाज होते हैं (1) प्राकृतिक, दीर्घकालिक, स्थायी समाधान (2) आयुर्वेदिक, मध्यकालिक, आंशिक समाधान (3) एलोपैथिक, अल्पकालिक, तत्काल क्षणिक समाधान। ज्ञान क्रान्ति प्राकृतिक समाधान है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिन्तन शक्ति का विस्तार करना होता है। हम सब पूरी ताकत से इस ज्ञान क्रान्ति अभियान में लगे हैं और सफल हैं। (2) अन्ना जी की टीम का अभियान आयुर्वेदिक इलाज है। इन्होंने वर्तमान संसदीय लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा के उद्देश्य से चुनौती दी है। बाबा रामदेव ने अनावश्यक बीच में कूदकर राजनेताओं का मनोबल बढ़ा दिया अन्यथा सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। अब भी समय है कि बाबा रामदेव अपनी अनावश्यक महत्वकांक्षाएँ छोड़कर इस आंदोलन को बाहर से समर्थन देना शुरू कर दें। यदि रामदेव जी समाधान के इच्छुक हैं तो यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। (3) राजनीति में इमानदार और संदेहास्पद का चरित्र विभाजन करके इमानदार लोगों को प्रोत्साहन तथा संदेहास्पद लोगों की आलोचना का अभियान समस्या का एलोपैथिक समाधान है। इसमें हम दलगत राजनीति से उपर उठकर मनमोहन सिंह, नीतिश कुमार की टीम की प्रशंसा और लालू, मुलायम, मायावती की टीम की आलोचना करें। हमारे समक्ष तीनों विकल्प खुले हैं। जो व्यक्ति जैसी क्षमता रखता है और जिस प्रणाली पर उसे विश्वास हो उस दिशा में वह सक्रिय हो सकता है। मैं तो ज्ञान क्रान्ति अभियान की दिशा में पूरी ताकत से लगा हूँ। साथ ही अन्ना जी के आंदोलन का सहयोगी हूँ तथा मनमाहेन की टीम का प्रशंसक हूँ।

अन्त में मेरा रामदेव जी से निवेदन है कि वे भारत की वर्तमान संसदीय प्रणाली को लोक स्वराज्य प्रणाली की ओर ले जाने के अन्ना हजारे आंदोलन को बिना शर्त बाहर से समर्थन करें। अन्यथा उनका वही हाल होगा कि आधी छोट एक पर धावे, एक मिले न आधी पावे।

कायरता की पटकथा पर माओवाद का मातम

—संजय द्विवेदी

भारतीय राज्य की निर्ममता और बहादुरी के किस्से हमें दिल्ली के रामलीला मैदान में देखने को मिले। यहाँ भारतीय राज्य अपने समूचे विद्रूप के साथ अहिंसक लोगों के दमन पर उतारू था। लेकिन देश का एक इलाका ऐसा भी है जहाँ इस बहादुर राज्य की कायरता की कथा लिखी जा रही है। यहाँ हमारे जवान रोज मारे जा रहे हैं और राज्य के हाथ बंधे हुए लगते हैं।

बात बस्तर की हो रही है, जहाँ गुरुवार की रात 9 जून 2011 को नक्सलियों ने 10 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। ठीक कुछ दिन पहले 23 मई 2011 को वे एक एडीशनल एसपी समेत 11 पुलिसकर्मियों को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मौत के घाट उतार देते हैं। गोली मारने के बाद शवों को क्षत विक्षत कर देते हैं। बहुत

वीभत्स नजारा है। माओवाद की ऐसी सौगातें छत्तीसगढ़ में आम हो गई है। बाबा रामदेव के पीछे पड़े हमारे गृहमंत्री पी० चिदंबरम और केंद्रीय सरकार के बहादुर मंत्री क्या नक्सलवादियों की तरफ भी रूख करेंगे?

भारतीय राज्य के द्वारा पैदा किए गए भ्रम का सबसे ज्यादा फायदा नक्सली उठा रहे हैं। उनका खूनी खेल नित नये क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है। निरंतर अपना क्षेत्र विस्तार कर रहे नक्सल संगठन हमारे राज्य को निरंतर चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनका निशाना दिल्ली है। 2050 में भारतीय राज्य सत्ता पर कब्जे का उनका दुस्वप्न बहुत प्रकट है किन्तु जाने क्यों हमारी सरकारें इस अधोषित युद्ध के समक्ष अत्यंत विनीत नजर आती हैं। एक बड़ी सोची समझी साजिश के तहत नक्सलवाद को एक विचार के साथ जोड़ कर विचारधारा बताया जा रहा है। क्या आतंक का भी कोई वाद हो सकता है? क्या रक्त बहाने की भी कोई विचारधारा हो सकती है? राक्षसी आतंक का दमन और उसका समूल नाश ही इसका उत्तर है। किन्तु हमारी सरकारों में बैठे कुछ राजनेता, नौकरशाह, मीडिया कर्मी, बुद्धिजीवी और जनसंगठनों के लोग नक्सलवाद को लेकर समाज को भ्रमित करने में सफल हो रहे हैं। गोली का जबाब, गोली से देना गलत है— ऐसा कहना सरल है किन्तु ऐसी स्थितियों में रहते हुए सहज जीवन जीना भी कठिन है। एक विचार ने जब आपके गणतंत्र के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है तो क्या आप उसे शान्ति प्रवचन ही देते रहेंगे। आप उनसे संवाद की अपीलें करते रहेंगे और बातचीत के लिये तैयार हो जायेंगे। जबकि सामने वाला पक्ष इस भ्रम का फायदा उठाकर निरंतर नई शक्ति अर्जित कर रहा है।

देश को तोड़ने और आम आदमी की लड़ाई लड़ने के नाम पर हमारे जनतंत्र को बदनाम करने में लगी ये ताकतें व्यवस्था से आम आदमी का भरोसा उठाना चाहती हैं। अफसोस, व्यवस्था के नियम इस सत्य को नहीं समझ रहे हैं। वे तो बस शान्ति प्रवचन करते हुए लोकतंत्र की कायरता के प्रतीक बन गये हैं। अपने भूगोल और अपने नागरिकों की रक्षा का धर्म हमें लोकतंत्र ही सिखाता है। निरंतर मारे जा रहे आदिवासी समाज के लोग और हमारे पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान आखिर हमारी पीड़ा का कारण क्यों नहीं है? जब भारतीय राज्य को अपनी कायरता की ही पटकथा लिखनी है तो क्या कारण है कि अपने जवानों के जंगलों में ढकैल रखा है? इन इलाकों से सुरक्षा बलों को वापस बुलाइये क्योंकि वे ही नक्सलियों के सबसे बड़े शत्रु हैं। नक्सलियों के निशाने पर आम आदमी, पुलिस व सुरक्षाबलों के जवान हैं। शेष सरकारी अमले से उनका कोई संघर्ष नहीं दिखता। वे सबसे लेवी वसूलते हुए जंगल में मंगल कर रहे हैं और एक न पूरा होने वाला स्वप्न देख रहे हैं। किन्तु जिस राज्य पर उनके स्वप्न भंग की जिम्मेदारी है, वह क्या कर रहा है।

विचारधारा के आधार पर बटे देश में यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे सवाल पर भी हम एक आम सहमति नहीं बना पा रहे हैं। प्लीज, अब इसे लोकतंत्र का सौंदर्य या विशेषता न कहिये। क्योंकि जहाँ हमारे लोग मारे जा रहे हो वहाँ भी हम असहमति के सौंदर्य पर मुग्ध हैं तो यह चिंतन बेहद अमानवीय है। हिंसा का कोई भी रूप, वह वैचारिक रूप से कहीं से भी प्रेरणा पाता हो, आदर योग्य नहीं हो सकता। यह हिंसा के खिलाफ हमारी सामूहिक सोच बनाने का समय है। आतंकवाद के विविध रूपों से जूझता भारत और अपने अपने आतंक को सैद्धान्तिक जामा व वैचारिक कवच पहनाने में लगे बुद्धिजीवी इस देश के लिये सबसे बड़ा खतरा है।

आदिवासी समाज को निकट से जानने वाले जानते हैं कि यह दुनिया का सबसे निर्दोष समाज है। ऐसे समाज की पीड़ा को देखकर भी न जाने कैसे हम चुप रह जाते हैं। पर यह तय मानिये कि इस बेहद अहिंसक, प्राकृतिक समाज के खिलाफ चल रहा नक्सलवाद अभियान एक मानवताविरोधी अभियान भी है। हमें किसी भी रूप में इस सवाल पर किन्तु परन्तु जैसे शब्दों के माध्यम से बाजीगरी दिखाने का प्रयास नहीं करना चाहिये। भारत की भूमि के वास्तविक पुत्र आदिवासी ही हैं, कोई विदेशी विचार उन्हें मिटाने में सफल नहीं हो सकता। उनके शान्त जीवन में बंदूकों का खलल, बारूदों की गंध हटाने का यही सही समय है। केन्द्र और राज्य सरकारों में समन्वय और स्पष्ट नीति के अभाव ने इस संकट को और गहरा किया है। राजनीति की अपनी चाल और प्रकृति होती है। किन्तु बस्तर से आ रहे संदेश यह कह रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र यहाँ एक कठिन लड़ाई लड़ रहा है उसका सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमारी सरकारों और राजनीति की प्राथमिकता में आदिवासी कहीं आते हैं। क्योंकि आदिवासियों की अस्मिता के इस ज्वलंत प्रश्न पर आदिवासियों को छोड़कर सब लोग बात कर रहे हैं, इस कोलाहल में आदिवासियों के मौन को पढ़ने का साहस क्या हमारे पास है?

समीक्षा— मैं आपके लेख की मूल भावना से पूरी तरह सहमत हूँ। किन्तु बाबा रामदेव का चार जून का रामलीला मैदान का अनशन और बस्तर के आतंकवाद की तुलना नहीं हो सकती। यह अनशन एक अस्पष्ट मुद्दे पर किया गया आंदोलन था जबकि नक्सलवाद एक सुनियोजित हिंसक सत्ता संघर्ष। मैं सहमत हूँ कि रामलीला मैदान के अनशन की अपेक्षा बस्तर की समस्या कई गुना अधिक चिन्ताजनक है किन्तु यदि किसी कारण वश बस्तर में कायरता दिखानी पड़ रही है तो दिल्ली को भी अव्यवस्था में झोंक दिया जाय यह ठीक नहीं। बाबा रामदेव जिस काले धन के लिये निर्णायक संघर्ष पर उतारू थे उन्हीं बाबा रामदेव ने बस्तर मुक्ति को मुद्दा बनाकर अनशन क्यों नहीं किया। क्या बस्तर भारत का अंग नहीं? क्या बस्तर की समस्या काले धन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा गंभीर नहीं?

बस्तर के आतंक की पटकथा में अब तक दो पात्रों के बीच के सत्ता संघर्ष की गंध आ रही है जिसमें एक ओर है मनमोहन सिंह सरकार और दूसरी तरफ है मनमोहन सिंह को येन केन प्रकारेण असफल अयोग्य सिद्ध करके राहुल गांधी को बिठाने की जल्दबाजी। मनमोहन सिंह का हर कदम सुनियोजित तथा लोक तांत्रिक है तो राहुल की टीम का बचकाना तथा घातक। मेरे पास कोई स्पष्ट जानकारी तो है ही नहीं किन्तु जिस तरह राष्ट्रीय सलाहकार परिषद को प्रोत्साहित किया जा रहा है अथवा दिग्विजय सिंह को छुट्टा सांड के समान कहीं भी मुँह मारने की छूट दी गई है वह संदेह तो पैदा करती ही है कि मनमोहन सिंह जी को बदनाम करने की सुनियोजित चालें चली जा रही हैं। इन चालों में सोनिया जी शामिल हो भी सकती हैं और शायद न भी हों। राहुल गांधी तो अभी नौसिखिया हैं। हो सकता है कि वह सत्ता के लोभ में न पड़कर वास्तव में मनमोहन सिंह को गलत मानने लगा हो। बात चाहे जो हो किन्तु खतरनाक है। अभी तो बस्तर का मामला कठिन होते हुए भी हाथ से बाहर नहीं गया है किन्तु उस दिशा में जा जरूर रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो अब केन्द्र में अस्तित्व ही खो रही है। इसलिये अब तो आप जैसे जागरूक लोगों को ही आगे आना चाहिये। साथ देने में तो हम सब हैं ही यह मामला किसी भी रूप में आदिवासी गैर आदिवासी का नहीं है। फिर भी यदि मामले को अधिक हाईलाइट करने के लिये आदिवासी शब्द शामिल किया गया है तो कोई गलत नहीं। यह सच है कि बस्तर के युद्ध क्षेत्र बनने से वहाँ जिन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी वे गरीब भी हैं ग्रामीण भी और सम्बैधानिक भाषा में आदिवासी भी। अतः इस मामले को हर तरह से सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिये। मेरा तो मत है कि भविष्य में नक्सलवादियों के द्वारा की गई हत्याओं के शिकार मृतकों के शव राहुल गांधी की टीम अथवा विशेषकर दिग्विजय सिंह के पास भेज दिये जाने चाहिये। शायद इनकी आत्मा जगे और ये राजनीति से उपर उठकर राष्ट्र और समाज के विषय में भी सोचना शुरू करें।

(1) श्री चिन्मय व्यास, मालदेवता, देहरादून, उत्तरांचल

सुझाव अंक 221 में आपने अपनी भूमिका में बताया कि अन्ना हजारे को समर्थन है मगर रामदेव को नहीं क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर है। रामदेव या अन्य कोई भी विचारधारा वाले यदि देश या मानवता के समग्र व्यापक हित के लिये कोई अहम मुद्दे के लिये शान्ति पूर्ण तरीके से अहिंसक तरीके से आंदोलन करते हैं तो उसे समर्थन देना चाहिये। भ्रष्टाचार कालाधन भाई भतीजावाद, अफसर शाही, गरीबी, बेरोजगारी, प्रदूषण वृद्धि, वन कटाई या अन्य कोई मुद्दा जो आज की ज्वलंत समस्या है और सार्वजनिक हित का है तो हमें सैद्धान्तिक मतभेद को सुरक्षित रखते हुए भी उसे समर्थन देना चाहिये ताकि बुराई को दूर करने में देश की जागरूक शक्ति समग्र रूप से उस काम में लगे। सिद्धान्त के नाम पर हम मूक रहें यह ठीक नहीं। सब अच्छी ताकतों को अच्छे काम के लिये एक जुट हो जाना चाहिये। छोटे छोटे दायरों में अच्छी शक्तियाँ बटी न रहे। बनवारी लाल जी अण्णा हजारे, खैरनारजी, किरण वेदी, या अन्य संस्थाएँ व लोग सबको अच्छे काम के लिये व्यापक समर्थन देना चाहिये।

उत्तर— मैं कभी भी रामदेव जी का न आलोचक रहा न विरोधी। मैं उनका प्रशंसक रहा हूँ। किन्तु मैं इस बात के पक्ष में नहीं कि यह आंदोलन टुकड़ों के बटे। मेरी इच्छा है कि सब लोग मतभेद भूलकर एक जगह इकट्ठे हो। आप जानते हैं कि इस विषय पर हमलोगों की टीम ने सबसे अधिक प्रयास किया है। किन्तु हम अपने प्रयासों को आंदोलन में नहीं बदल सके। अब यदि अन्ना जी की टीम उस दिशा में आगे बढ़ती है तो हमें खुश होना चाहिये न कि अन्ना जी के प्रयत्नों में अनावश्यक छेद खोजने चाहिये। आपके पत्र के बाद स्थितियाँ बदल चुकी हैं इसलिये आपके अगले पत्र का इंतजार करूंगा। रामदेव जी के आंदोलन में कहीं भी व्यवस्था परिवर्तन नहीं है। हमारे देश की विधायिका ने मंत्रिमंडल के माध्यम से कार्यपालिका पर अपना अधिकार जमा रखा है और संसद के माध्यम से संविधान संशोधन पर भी। यदि कार्यपालिका तथा संविधान संशोधन दोनों पर विधायिका का अंकुश हो जाय तब लोकतंत्र को आदर्श कैसे कहें? इसलिये हमारी लड़ाई विधायिका के आदेशों के खिलाफ न होकर अधिकारों के खिलाफ होना चाहिये। सरकार के गलत आदेशों के खिलाफ लड़ाई लड़ना किसी भी रूप में व्यवस्था परिवर्तन नहीं है जब तक उस आदेश को बदलने का अन्तिम अधिकार विधायिका के पास ही रहता है। हम तो यह चाहते हैं कि विधायिका या सरकार के अधिकारों की समीक्षा हो। यह घोषित हो कि राज्य अथवा संसद के अधिकारों की सीमाएँ क्या हो? यदि

आवश्यकता पड़े तो संविधान संशोधन के विधायिका के अधिकार भी संशोधित हो। रामदेव जी के आंदोलन में सरकार के गलत आदेशों के विरुद्ध ही संघर्ष की बात सीमित है, जो हमारा उद्देश्य नहीं। अन्ना जी के आंदोलन की दिशा राज्य के अधिकारों की समीक्षा की ओर मुड़ी है। इसलिये हम अन्ना जी और रामदेव जी में फर्क कर रहे हैं।

(2) श्री राजेन्द्र भारतीय, महालक्ष्मी नगर, इन्दौर म0प्र0

ज्ञान तत्त्व अंक 220, प्राप्त हुआ। इस अंक के पृष्ठ 37 पर श्री राम जी लाल अरोडा अजमेर राजस्थान के एक प्रश्न के उत्तर के तहत बिन्दु क्र 0 :5 के अंतर्गत आपकी ये चार पक्तियाँ अंकित हैं " धर्म संकट में है धर्म की रक्षा करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। हिन्दू मुसलमान इसाई सिक्ख सभी धर्म प्रेमियों को एक जुट होकर अधर्म के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर देना चाहिये। इन पक्तियों पर मन में जिज्ञासा स्वरूप कुछ प्रश्न उभर आये हैं जो इस प्रकार हैं। आपकी दृष्टि में धर्म क्या है उसका स्वरूप कैसा हो? कौन सा कैसा धर्म संकट में है? हिन्दू मुसलमान इसाई सिक्ख धर्मावलंबियों को आपने धर्म प्रेमियों के रूप में आह्वान कर किस धर्म के लिये एक जुट होकर संघर्ष करने हेतु कहा है? क्या वह उपयुक्त धर्म मतावलंबियों के धर्म से भिन्नता रखता है? क्या ये सब भिन्न धर्मानुयायी एक जुट हो सकेंगे? अगर हाँ तो उनके एकजुट होने की ज्ञान प्रेम भाव विचार कर्म मय कौन सा सिद्धान्त या कौन सी कैसी योजना आधार भूमि हो सकेगी? इसका नाम क्या होगा?

आपने आगे लिखा है कि आर्य समाज ने मुझे बचपन में ही इसाई होने से बचा लिया है। इस पर जिज्ञासा है कि इसाई धर्म की ऐसी कौन सी बातें थी जिन से प्रभावित और आकर्षित होकर आप बचपन में ही इसाई बनना चाहते थे? आर्य समाज की किन बातों ने आपको इसाई धर्म के प्रभाव और आकर्षण से मुक्त कराया?

उत्तर— धार्मिक आधार पर व्यक्ति तीन प्रकार के होते हैं। (1) जो ऐसे काम करते हैं जो उन्हें समाज के प्रति करने चाहिये (2) जो ऐसे काम नहीं करते जो समाज के प्रति करने चाहिये। (3) जो ऐसे काम करते हैं जो उन्हें समाज के प्रति नहीं करने चाहिये। पहले प्रकार को धार्मिक, दूसरे को अधार्मिक तीसरे को धर्मविरोधी कहा जाता है। धार्मिक और अधार्मिक लोग हिन्दू मुसलमान इसाई विचारधाराओं में बटे हो सकते हैं किन्तु धर्म विरोधी लोग हिन्दू, मुसलमान, इसाई में शामिल नहीं हो सकते क्योंकि वे तो ऐसे कार्यों में संलग्न हैं जो निषिद्ध हैं।

मोटे तौर पर सामान्य परिस्थितियों में पांच प्रकार के कार्य धर्म विरोधी माने जा सकते हैं (1) चोरी, डकैती, लूट (2) बलात्कार (3) मिलावट, कमतौल (4) धोखा, जालसाजी (5) हिंसा और आतंक। छठवाँ कोई भी आचरण धर्म विरोधी नहीं होता। ये पांच काम भी देश काल परिस्थिति अनुसार अर्थ बदलते रहते हैं।

धर्म के आधार पर संस्थाएँ तो बन सकती हैं किन्तु संगठन नहीं क्योंकि संगठन में अधिकार और कर्तव्य दोनों जुड़ा रहता है और संस्था में अधिकार भाव होता ही नहीं। हिन्दू मुसलमान इसाई सिक्ख यदि संगठन के रूप में स्थापित हैं तो निश्चित रूप से वे धार्मिक तो नहीं हो सकते भले ही अधार्मिक हो या धर्म विरोधी। इस्लाम में मुठी भर सुफी लोगो को छोड़कर बहुत बड़ी संख्या धर्म को संगठन मानकर चलने वालों की है। इसाईयो में संगठन मानने वाले की संख्या कम है और हिन्दुओं में नगण्य है।

वर्तमान समय में धर्म विरोधी लोग लगातार ताकतवर होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब तो हिन्दू मुसलमान इसाई के नाम पर संगठन भी बनते जा रहे हैं तथा इन संगठनों में धर्म विरोधी आचरण करने वाले लोग धड़ल्ले से शामिल हो रहे हैं। धर्म की पहचान आचरण से हटकर चोटी दाढ़ी भाषा वस्त्र आदि तक सिमटती जा रही है। इसलिये मैंने लिखा कि सभी धर्म प्रेमियों को एक जुट होना चाहिये। मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा होना अभी संभव नहीं दिखता किन्तु हमें प्रयत्न जारी रखना चाहिये। स्वामी सत्य भक्त जी ने इस दिशा में काफी कुछ प्रयत्न किये। यदि बीज बचा रहा तो भविष्य में कोई खाद पानी देकर बीज को पेड़ की दिशा में बढ़ा सकता है। बहुत बचपन में छुआछूत का विरोध करने के कारण उस समय के ब्राम्हणों से मेरा टकराव हो गया था। स्थानीय चर्च वालों के अच्छे व्यवहार ने मुझे आकर्षित किया और मैं इसाईयत की दिशा में कदम बढ़ाया। मैं इसाईयत के गुण दोष की समीक्षा करके उधर नहीं जा रहा था बल्कि वह एक परिस्थिति जन्य घटना थी। इसी तरह आर्य समाज के गुण दोषों की व्यापक समीक्षा भी न करके परिस्थिति जन्य घटना के आधार पर मैं आर्य समाज से जुड़ा। बाद में मुझे आर्य समाज की एक बात ने प्रभावित किया कि सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने को सदा तैयार रहना चाहिये। वर्तमान समय में आर्य समाज का दसवाँ नियम मुझे बहुत प्रभावित करता है कि व्यक्ति को व्यक्तिगत मामलों में निर्णय की अधिकतम स्वतंत्रता होनी चाहिये। तथा सामूहिक मामलों में सब मिलकर ही निर्णय करें। आर्य समाज का यह नियम ही लोक स्वराज्य का महत्वपूर्ण कदम है।

(3) श्री ओमपल सिंह जी मेरठ

ज्ञान तत्त्व दो सौ चौबीस में कुछ गंभीर चर्चाएँ की गई हैं। कुछ प्रश्न भी उठते हैं आप इन प्रश्नों को आधार बनाकर विस्तृत समीक्षा करने की कृपा करें—

- (1) समाज व्यवस्था और समाजवाद में क्या अंतर है
- (2) धर्म और पूजा पद्धति का अंतर स्पष्ट करें
- (3) व्यक्ति के मूल अधिकारों का निर्धारण समाज का अधिकार है या राज्य का। संविधान की इसमें क्या भूमिका है?
- (4) किसी व्यक्ति के बालिग होने या न होने का निर्णय कौन करेगा।

उत्तर— व्यक्ति, परिवार और समाज के आपसी सम्बन्धों के कर्तव्य, दायित्व और अधिकारों का समन्वय समाज व्यवस्था है। समाज व्यवस्था अनुशासन से चलती है तथा शासन मुक्त होती है। जब व्यक्ति, परिवार और समाज में से कोई इकाई किसी अन्य इकाई की सहमति के बिना उसके अधिकारों की सीमाओं में हस्तक्षेप करती है तब राज्य की भूमिका शुरू होती है अन्यथा नहीं। भारत में ऐसी ही व्यवस्था थी किन्तु कई सौ वर्षों की गुलामी ने समाज व्यवस्था को कमजोर करके राज्य द्वारा स्वयं को समाज घोषित करने की मानसिकता बनाई जो अब तक जारी है।

समाजवाद शब्द की उत्पत्ति भारत से न होकर यूरोप से है। समाजवाद कोई विचारधारा रही अथवा मजबूरी यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। ऐसा लगता है पूंजीवाद के विरुद्ध साम्यवाद की निरंतर बढ़ती सफलताओं से चिन्तित होकर पूंजीवादी देशों ने समाजवाद शुरू किया। साम्यवाद तथा समाजवाद राजनैतिक शक्ति के केन्द्रीकरण तथा आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पोषक हैं। किन्तु साम्यवाद तथा समाजवाद में खास फर्क यह है कि साम्यवाद बलप्रयोग को उचित मानता है जबकि समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके पर विश्वास करता है। मुझे ऐसा लगता है कि साम्यवाद की बाढ़ को रोकने के उद्देश्य से समाजवाद लाने के प्रयास शुरू हुए होंगे। पूंजीवाद और लोकतंत्र भयभीत हो गये होंगे कि यदि समाजवाद नहीं आया तो साम्यवाद पूरी दुनियाँ को निगल जायगा। इसलिये ही समाज शब्द को जोड़कर यह नया शब्द बनाया गया। समाजवाद समाज व्यवस्था को कमजोर करके राज्य व्यवस्था को मजबूत करता है। समाजवाद साम्यवाद से बचने का तो माध्यम है किन्तु राज्य को समाज के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का मार्ग खोलता है। वर्तमान समय में भारत में साम्यवाद अप्रासंगिक हो गया है। अब तो भारत को खतरा है पूंजीवाद से। पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद अधिक घातक है। इसलिये पूंजीवाद के स्थान पर समाजीकरण प्रणाली पर सोचा जाना उचित होगा।

धर्म और पूजा पद्धति बिल्कुल भिन्न विषय हैं। किसी अन्य के हित में किये गये निःस्वार्थ कार्य को धर्म कहते हैं। पूजा पद्धति नितान्त व्यक्तिगत हित का मामला है। जबकि धर्म नितान्त, सामाजिक। पूजा पद्धति में व्यक्ति स्वयं को धर्म की ओर प्रेरित करने का प्रयत्न करता है। भारत में चूँकि धर्म पूजा पद्धति से न जुड़कर सीधा आचरण से जुड़ा था इसलिये नास्तिक भी धर्मात्मा हो सकता था। अन्य संगठन प्रधान धर्मों में यह छूट नहीं। वर्तमान समय में हिन्दू धर्मावलंबी बहुमत भी पूजा पद्धति को ही धर्म मानने लगा है। हिन्दुआ का एक छोटा समूह तो संगठन को भी धर्म के लिये आवश्यक गुण बताने लगा है। हिन्दू बहुमत का कर्तव्य था कि वह धर्म की विकृत परिभाषा वालों को धर्म की वास्तविक परिभाषा का ज्ञान कराता जिसके विपरीत वह स्वयं ही उस विकृत परिभाषा का पैरोकार बनने लगा यह दुःखद है।

व्यक्ति के मूल अधिकारों का निर्धारण न समाज कर सकता है न राज्य। व्यक्ति के मूल अधिकार प्रकृति प्रदत्त हैं दीर्घकालिक हैं, अपरिवर्तनीय हैं। यह गलत बात प्रचारित हुई है कि संविधान व्यक्ति को मूल अधिकार देता है। संविधान को तो स्वयं को अधिकार समाज ने दिये हैं। कोई भी अधिकार संविधान का अपना नहीं। जब उसका अपना स्वयं का कुछ नहीं तो वह दूसरों को क्या देगा? संविधान व्यक्ति के मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी मात्र देता है। यह सुरक्षा की गारंटी उसका दायित्व है स्वैच्छिक कर्तव्य मात्र नहीं। पश्चिम के विद्वान मूल अधिकार की परिभाषा ठीक ठीक न समझने के कारण उसे अस्पष्ट बना दिये। साम्यवाद तथा इस्लाम तो मूल अधिकार मानता ही नहीं। यह सिर्फ भारत की अवधारणा है। दुर्भाग्य से हमारे संविधान निर्माताओं ने भी पश्चिम की नकल करके मूल अधिकार की परिभाषा को विकृत कर दिया।

मूल अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत होते हैं। समाज सरकार या संविधान व्यक्ति के इन व्यक्तिगत अधिकारों में बिना उसकी सहमति के किसी भी स्थिति में तब तक कोई कटौती नहीं कर सकता जब तक उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों पर आक्रमण न किया हो। यदि किसी व्यक्ति ने परिवार या समाज के नियमों को तोड़ा हो तब भी उस व्यक्ति के पारिवारिक या सामाजिक अधिकारों में ही कटौती हो सकती है, मूल अधिकारों में नहीं। किसी व्यक्ति ने अपनी बेटी को पत्नी बना लिया जो एक

समाज विरोधी कार्य है। हम उस व्यक्ति को समाज बहिष्कृत तो कर सकते हैं किन्तु पीट नहीं सकते क्यों कि पीटना उस व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। यदि वह व्यक्ति बलात्कार करे तब उसे राज्य के माध्यम से दण्डित कराया जा सकता है क्योंकि उसने किसी अन्य के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ना समझी में पश्चिम की नकल करके मूल अधिकार की अवधारणा बदल दी।

किसी व्यक्ति के बालिग होने का निर्णय पारिवारिक मामलो में परिवार करेगा, सामाजिक मामलो में समाज और संवैधानिक मामलों में कानून। किसी व्यक्ति को किस उम्र में वोट का अधिकार दिया जाय यह कानून तय करेगा। किसी बालक को किस उम्र में विवाह की छूट दी जाय यह परिवार और समाज तय करेंगे, सरकार नहीं। किसी व्यक्ति के बालिग होने ने होने का निर्णय कुछ विषयों में तो सामान्य हो सकते हैं किन्तु कुछ विषयों में उस व्यक्ति की क्षमता योग्यता के आधार पर तय करना होगा। हर मामले में सरकार को दखल नहीं देना चाहिये।

(4) ए० पी० द्विवेदी, रीवा मध्य प्रदेश

(1) बाबा रामदेव जी के आंदोलन के आधार पर भ्रष्टाचार और काले धन को वापस लाकर अपने देश का पैसा यदि जिसने जमा किया है वह अपना सही तरीके से व्योरा देता है तो वह अपना धन वापस ले ले। यदि कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि यह पैसा हमारा है और कहाँ से मिला तो उस पैसों को देश के राष्ट्रीय खजाने में जमा करने को कह रहे हैं तो कौन सा गलत कह रहे हैं। सरकार के लोग यदि यह गलत मानते हैं तो देश की एक सौ बीस करोड़ के लगभग जनता को अपना सही जबाब दे।

(2) मेरी समझ से बाबा रामदेव जी के द्वारा किया जा रहा भ्रष्टाचार का काला धन वापस लाने का मामला हो या अन्ना हजारे का लोकपाल बिल या भ्रष्टाचार मिटाने का मुद्दा ही। दोनों मुद्दों पर तंत्र व सरकार कोई ठोस कार्यवाही करना ही नहीं चाहती तथा विपक्ष में भी बैठे सदन के लोग कार्यवाही कराना नहीं चाहते क्योंकि हमारी समझ से यदि लोकतंत्र में अपराध करना गलत है तो उससे भी बड़ा अपराध, अपराधी, को सहायता करना, और अपराध सहना भी है।

(3) मैं इस समय की सामाजिक वा लोकतांत्रिक व्यवस्था से पूर्ण रूपेण सहमत नहीं हूँ। क्योंकि वर्तमान समय में हमारी समझ से भावनात्मक वा वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। यदि वर्तमान समय में सुविचार, भावनात्मक और बौद्धिक तीनों का विचार मंथन कर देश हित वा समाज हित में कार्य किया जाय तो वर्तमान समय में चल रहे भ्रष्टाचार वा वर्चस्व रूपी अहं को समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान समय में भ्रष्टाचार वा वर्चस्व रूपी अहं वा धन रूपी ताकत और तंत्र रूपी पद ये तीनों समाज वा देश को दल दल रूपी कीचड़ में ढकेल रहे हैं। क्योंकि ये तीनों जो दुर्गुण हैं मनुष्य के जीवन में समाहित हो चुका है इन तीनों दुर्गुणों को मनुष्य रूपी जीवन से त्यागना होगा तभी देश में सामन्जस्य बन सकता है। जिस दिन यह विचार समस्त मानव जीवन में राजनैतिक सामाजिक संगठन तथा धार्मिक लोगों के जीवन में एक राष्ट्रभाव उत्पन्न हो जायगा। तो हमारे देश के महान पुरुषों का सपना साकार हो जायगा तथा एक अच्छे देश के रूप में उभर कर विश्व शक्ति के रूप में हम देख सकते हैं।

(4) हमारे विचार से 4/6/11 को बाबा रामदेव जी के द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार वा काले धन को वापस लाने का आंदोलन में सरकार और बाबा के बीच जो घटना हुई उसमें हमारी समझ से सरकार में बैठे सरकारी तंत्र (1) पक्ष और विपक्ष (2) समस्त सामाजिक संगठन (3) धर्म की परिकल्पना लिये समाज सुधार के विचार रखने वाले धार्मिक संगठन 4/6/11 की हुई घटना के कहीं न कहीं तीनों दोषी हैं। कोई कम हो सकता है तो कोई ज्यादा। क्योंकि 4/6/11 की घटना में बाबा रामदेव जी और सरकार के बीच घटित घटना में बीच के लोग चाहे राजनैतिक विपक्ष या अन्य सामाजिक संगठन या धार्मिक संगठन हो वह मूक दर्शक बन कर बैठा देख और सोच रहा था कि बाबा रामदेव जी या सरकार के बीच हो रहे सामाजिक सुधार या भ्रष्टाचार खत्म या काले धन वापस के क्या परिणाम आ सकते हैं क्योंकि बाबा रामदेव जी के इस आंदोलन में सुअस्पष्टता नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि यह आंदोलन एक भावनात्मक रूप से तैयार आंदोलन था। यदि इसी आंदोलन को भावना और विचार मंथन करके किया जाता तो परिणाम पहले ही परिलक्षित हो जाता क्योंकि इसका मूल कारण बाबा जी के क्रिया कलापों से ही पता नहीं चल रहा है। यदि बाबा रामदेव जी किसी के दबाव में नहीं थे या मरने से नहीं डरते, तो बाबा रामदेव जी भारत की जनता या अपने कार्यकर्ताओं से अपने द्वारा किया या कराये गये कृत्यों को क्यों छुपाया? बाबा जी के पास सरकार द्वारा किये गये कृत्यों को उजागर करने का काफी समय था। इसमें कुछ ना कुछ बाबा रामदेव की कमजोरी जरूर रही होगी। जिसके केवल सरकार के कुछ लोगों वा बाबा रामदेव जी ही जानते हैं जिसके कारण यह घटना हुई। यदि बाबा जी जंतर मंतर में अपने एक लाख कार्यकर्ताओं के बीच स्टेज पर वा देश में कई सामाजिक संगठन वा धार्मिक संगठन या समाज के लोग बाबा के पीछे खड़े थे तो बाबा रामदेव जी को स्टेज से इसे तरह छलांग लगाकर कूद कर भागने की क्या जरूरत पड़ी। बाबा रामदेव जी उस समय स्टेज पर बैठे रहते और अपने कार्यकर्ताओं या देश के लोगों को मीडिया के सामने उद्वोधन करते, ऐ देश के लोगों मेरे और आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर ले जा रहे हैं तो अब आप लोगों को लगता है कि गलत है तो हमारे साथ आप स्वयं आइये। छलांग लगाकर भाग दिये और इसके बाद कहीं नहीं दिखाई दिये और सीधे हरीद्वार पहुँचे। वहाँ पर मीडिया द्वारा सूचना प्रकाशित हुई जिसके परिणाम स्वरूप कार्यकर्ता भडके और सीधे सरकार के तंत्र से भिड़ गई जिसका परिणाम यह हुआ कि जो मोहें मारे ते मैं मारे और वेचारी भोली भाली जनता पिट गई और बाबा रामदेव जी हरीद्वार और सरकार अपनी जगह और दोना के तरफ से बेचारे कार्यकर्ता वा तंत्र की सेना कसरत वा हो हल्ला का रही है।

(5) सरकार यह बताये कि बाबा के द्वारा लिखाई गई चिट्ठी का खुलासा पहले क्यों नहीं किया ऐसी कौन सी मजबूरी सरकार के पास और बाबा रामदेव थी कि श्री बाल कृष्ण के द्वारा लिखवाई गई चिट्ठी का खुलासा समय रहते नहीं कर सके? इसमें दोनो की कमजोरी प्रकाशित हो रही है।

(6) यदि ऐसा नहीं है तो हमारी समझ से इस आंदोलन में हुए कृत्य को दोनो जन मीडिया के समक्ष एक स्टेज पर सामाजिक संगठनों या धार्मिक संगठनों तथा तंत्र में बैठे पक्ष विपक्ष वा समस्त जनता के सामने लाइव टेलिकॉस्ट प्रकाशित करते हुए अपना स्पष्ट विचार व कार्य का प्रकाशन वा उद्वोधन करें। जिससे सरकार और बाबा रामदेव के बीच की जो कमजोरी होगी वही समस्त देशवासियों के सामने परिलक्षित होने लगेगी। और इस भ्रष्टाचार को तंत्र और सरकार खत्म करना नहीं चाहती और बाबा जी पूर्ण तैयारी नहीं की।

(7) मेरी समझ से तो जो लोग इस भारत को एक सामाजिक मूलक वा समृद्ध भारत तथा देश से भ्रष्टाचार समाप्त होने की परिकल्पना सोचते हैं तो उन सभी सामाजिक संगठन या धार्मिक समाज वा राजनैतिक संगठन तथा मीडिया के लोगों को एक साथ बैठ कर भिन्न भिन्न विचारों से निकली हुई वाणी से भावनात्मक और विचारात्मक तथा ज्ञानात्मक इन तीनों के मंथन से जो सही उपयुक्त कार्य समाज हित (राष्ट्र) तथा देश हित में निकल कर आये उस पर एक साथ सब मिल कर कार्य करें तभी परिणाम अच्छा आयेगा। नहीं तो ये भ्रष्टाचार युक्त तंत्र के लोग हम सब को एक एक कर कुचल देंगे और एक छत्र राज्य करेंगे। और परिणाम यही हो जा रहा है।

कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर—

(1) प्रश्न— आपने ज्ञान तत्व दो सौ तेइस में वेद व्यथित जी द्वारा परमाणु उर्जा के विरुद्ध आंदोलन में सहभागी होने की आलोचना की है। अब पता चला है कि जर्मन सरकार ने भी सन दो हजार बाइस तक परमाणु उर्जा संयंत्र पूरी तरह बंद करने की घोषणा कर दी है। अब इस संबंध में आपकी क्या राय है?

उत्तर— जर्मन सरकार ने दस वर्षों में परमाणु उर्जा संयंत्र बंद करने की घोषणा की है यह सच तो है किन्तु यह भी सच है कि जर्मन सरकार ने परमाणु उर्जा को दस वर्षों में सौर उर्जा में बदलने की बात कही है न कि डीजल पेट्रोल कोयला में। आप लोग परमाणु उर्जा का विरोध करने का ठेका लिये दिखते हैं तभी तो आधी बात प्रस्तुत करते हैं। पहली बात तो यह है कि जर्मनी और भारत की आर्थिक स्थिति अलग अलग है। भारत जर्मनी की नकल नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि जर्मनी का बिजली उत्पादन परमाणु संयंत्र से सौर उर्जा की ओर बदल रहा है जबकि भारत का परमाणु उर्जा से कोयला डीजल पेट्रोल उर्जा संयंत्र की दिशा में। तीसरी खास बात यह है कि जर्मनी के संयंत्र अभी चालू हैं तथा दस वर्ष बाद बन्द करने की योजना है। जर्मनी अपनी योजना बदल भी सकता है। हमारी हालत अलग है। हमें अभी संयंत्र लगाने हैं। हम यदि नहीं लगायेंगे तो हम नीति बदल भी नहीं सकते। जर्मनी के समक्ष तत्काल संकट नहीं है तथा दस वर्ष बाद भी उसके विकल्प खुले हैं जबकि भारत के पास तत्काल संकट है तथा दस वर्ष बाद भी विकल्प बन्द हो रहे हैं। इसलिये जर्मनी से भारत की तुलना और अनुकरण नहीं करना चाहिये।

एक बात और है कि विश्व में भूकम्प के डर से परमाणु संयंत्र बन्द करने की कोई भगदड़ नहीं मची है। एक जर्मनी ने बन्द करने की मंशा जाहिर की है। वह भी सौर उर्जा के साथ। यह कोई ऐसी बात नहीं कि हम तत्काल ही दौड़ पड़ें। भारत में किसी भी विषय की समीक्षा करने का स्वभाव ही नहीं रहा। तुरन्त ही किसी भी विषय पर पक्ष विपक्ष में गुट बन जाते हैं और ऐसे गुट गिरोह में बदल जाते हैं। ये गिरोह तिल का ताड़ बनाकर अपना कथन सिद्ध करने में किसी भी सीमा तक लग जाते हैं। ये न कुछ सुनना चाहते हैं न समझना चाहते हैं। परमाणु उर्जा के विरोध में उठी आवाज में भी कुछ ऐसी आवाजें शामिल हैं जो स्वाभाविक न होकर प्रायोजित हैं। ऐसे लोग किसी भी हालत में भारत की उर्जा खपत को तो बढ़ते हुए देखना चाहते हैं किन्तु विधुत उत्पादन में हर समय रोड़ा अटकाते रहते हैं। यदि उर्जा की खपत कम करने का कोई

भी प्रयास होता है तो ये लोग उर्जा का मूल्य बढ़ने ही नहीं देते क्योंकि उर्जा का मूल्य बढ़ने का सर्वाधिक प्रभाव उन्ही सम्पन्न लोगों पर ज्यादा पड़ता है। जो इसका ज्यादा उपयोग करता है। उर्जा की खपत ज्यादा करने वालों का जीवन स्तर प्रतिवर्ष आठ से सोलह प्रतिशत तक बढ़ रहा है। यदि हम उन्नीस सौ सैतालीस के एक रूपये को आधार माने तो आज तिरसठ वर्ष बाद भी पेट्रोल का मूल्य एक रूपया सत्तर पैसा मिट्टी तेल का मूल्य सिर्फ अस्सी पैसा ,डीजल का एक रूपया पचीस पैसा तथा बिजली का एक रूपया पैतालीस पैसा हुआ है। इसके विपरीत यदि उस समय औसत जीवन स्तर एक था और कुल आबादी के तीन भाग गरीब तेतीस प्रतिशत , मध्यम तेतीस प्रतिशत तथा सम्पन्न तेतीस प्रतिशत में बाटे तो पिछले साठ वर्षों में जीवन स्तर में एक की तुलना में गरीब का एक दशमलव आठ , मध्यम वर्ग आठ दशमलव दो तथा सम्पन्न का चौसठ गुना बढ़ा है। कल्पना करिये कि मध्यम वर्ग का भी जीवन स्तर आठ गुना और बिजली का मूल्य एक रूपया पैतालीस पैसा मात्र ही बढ़ा है। अमीर आदमी, जो बिजली की ज्यादा खपत करता है उसके जीवन स्तर सुधार की तुलना में बिजली का मूल्य नगण्य ही है। मैं जो आंकड़े दे रहा हूँ ये मेरे आंकड़े न होकर सरकारी रेकार्ड से है। इनमें कही मामूली सा गणितीय हेर फेर संभव है। इस संबंध में विस्तार से मैं अपने लेख महगाई यथार्थ नहीं मात्र शब्द जाल में लिखूंगा या कोई प्रश्न होगा तो और समझा दूंगा।

एक प्रश्न उठता है कि भारत के अनेक बुद्धिजीवी विजली उत्पादन वृद्धि के इतने खिलाफ क्यों रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बुद्धिजीवी विद्वानों का एक बड़ा वर्ग साम्यवाद से संचालित है। साम्यवाद पेशेवर तरीके से अमेरिका विरोधी है। पिछले बीस वर्षों से साम्यवादियों की आर्थिक मजबूती भी खाड़ी देशों की ओर झुकी है तथा राजनैतिक भी। खाड़ी देश सब कुछ सहन कर सकते हैं किन्तु डीजल, पेट्रोल गैस का बिजली में बदलना बरदास्त नहीं कर सकते क्योंकि एकमात्र यही तो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके लिये खाड़ी के देश राजनैतिक ब्लैक मेलिंग भी कर सकते हैं और आवश्यकता अनुसार गुप्त धन देकर भारत में अपने एजेंट भी खड़े कर सकते हैं। भारत का दुर्भाग्य है कि यहाँ हर चीज बिकाउ है। कुछ विद्वान ही ऐसे हैं जो सुरक्षा कारणों से परमाणु विजली का विरोध करते हैं अन्यथा अधिकांश ऐसे हैं जो किसी न किसी बहाने बिजली उत्पादन का विरोध करते हैं चाहे वह कारखाना परमाणु बिजली का हो या कोयला आधारित। कुछ लोग तो पन बिजली योजना तक का विरोध करते देखे जाते हैं। सोचने की बात है कि ऐसे लोगों को यदि खाड़ी देशों से कोई प्रोत्साहन नहीं है तो वे क्यों हर मामले में इतनी दौड़ धूप करते हैं।

मेरे विचार में भारत की सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण है डीजल पेट्रोल मिट्टी तेल गैस आदि की आयात वृद्धि। यदि हम इन सबका मूल्य बढ़ा दें और बिजली बनाने में ताकत लगा दें तो आयात में उल्लेखनीय कमी संभव है। मैं परमाणु उर्जा का समर्थक नहीं। मैं तो चाहता हूँ कि मानवीय उर्जा की मांग बढ़े और कृत्रिम उर्जा का मूल्य बढ़े। किन्तु मैं डीजल पेट्रोल की उर्जा के ज्यादा खिलाफ हूँ बिजली की अपेक्षा कोयला, कोयला की अपेक्षा परमाणु तथा परमाणु की अपेक्षा सौर उर्जा के पक्ष में हूँ। जो लोग परमाणु उर्जा के विरुद्ध हैं किन्तु डीजल पेट्रोल गैस पर चुप हैं उनकी नीयत में खोट है। ऐसे खराब नीयत वालों की पोल खुलनी चाहिये।

नोट—

आप शुल्क भेजना चाहे तो चेक न भेजे क्योंकि 100 रूपये के चेक को कैसे कराने में 50 रूपया खर्च आ जाता है। मनिआर्डर भेजना सबसे आसान है।

पत्र व्यवहार या मनिआर्डर बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ भेजना ज्यादा अच्छा है। वैसे रामानुजगंज से भी कोई दिक्कत नहीं है।

पिछले दो महिनो में प्राप्त राशि—

शिवकुमार खंडेलवाल सेक्टर-14 सोनीपत से 300 रु०, भारत भूषण गर्ग गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, आचार्य धर्मेश्वर नंद सरस्वति गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, राहुल उपाध्याय गाजियाबाद उ०प्र० से 100रु०, वेद प्रकाश प्रजापति गाजियाबाद उ०प्र० से 100रु०, अमर पाल सिंह आर्य गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, वीर ब्रम्हा सिंह माथुर गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, महेश आर्य गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, श्री पप्पु जी चक्की वाले गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, श्री जगमाल सिंह गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, श्री पवन शर्मा बहादुर गंज गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, मूल चंद्र आर्य बहादुरगंज गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु० चंद्र प्रकाश पटवारी गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, अशोक कुमार लोधी गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, विक्रान्त भारती गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, सत्य विर सिंह गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, अजय दादा गाजियाबाद उ०प्र० से 100 रु०, रमेश चंद्र जोशी उज्जैन म०प्र० से 500 रु०, सिंहासन तिवारी गोपालगंज बिहार से 100 रु०, चिन्मय व्यास देहरादुन , से 100, चितरंजन भारती आसाम से 100 रु०, रामेश्वर गुप्ता सीतापुर छ०ग० से 50 रु० की राशि प्राप्त हुई है।